



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3, 2018/माघ 14, 1939

No. 45]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 2018/MAGHA 14, 1939

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 22 जनवरी, 2018

सं. टीएएमपी/40/2011-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा शालुक्खली, हल्दिया डाक-II पर, कोलकाता पत्तन न्यास की भूमि के लिये किराया अनुसूची की वैधता में इसके साथ संलग्न आदेशानुसार विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या. टीएएमपी/40/2011-केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास

- - -

आवेदक

गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जनवरी 2018, के 19 वें दिन को पारित)

यह मामला शालुक्खली, हल्दिया डाक-II पर, कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) की भूमि की किराया अनुसूची की वैधता में विस्तार करने से सम्बंधित है।

2.1 शालुक्खली, हल्दिया डाक-II पर, केओपीटी की भूमि की वर्तमान किराया अनुसूची, इस प्राधिकरण के 14 फरवरी, 2012 के आदेश संख्या टीएएमपी/44/2011-केओपीटी के द्वारा अनुमोदित की गयी थी। यह आदेश 14 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 64 में अधिसूचित किया गया था। किराया अनुसूची राजपत्र में आदेश कि अधिसूचना की तारीख 30 दिन पश्चात प्रभावी हो गयी थी और 13 अप्रैल 2017 तक 5 वर्ष की अवधि के लिये वैध थी।

2.2 तत्पश्चात, शालुक्खली, हल्दिया डाक-II पर, केओपीटी की भूमि की किराया अनुसूची की वैधता में इस प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क में शून्यता से बचने और उक्त आदेश में दिये गये कारणों से दो अवसरों पर विस्तार किया गया। पिछली बार, इस प्राधिकरण ने अपने 15 सितम्बर, 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/40/2011-केओपीटी द्वारा वैधता में 31 दिसम्बर, 2017 तक विस्तार किया गया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में 9 अक्तुबर, 2017 के राजपत्र संख्या 389 में अधिसूचित किया गया था। ऐसा करते समय, इस प्राधिकरण द्वारा केओपीटी को सरकार द्वारा जारी संशोधित भूमि नीति, 2014 का अनुसरण करते हुए 31 अक्तुबर, 2017 तक किराया अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव दायर करने की सलाह दी गयी थी।

3. इस पृष्ठभूमि में, केओपीटी ने 28 दिसम्बर, 2017 के अपने पत्र संख्या एडी/ई/1032/एसडी/ शालुक्खली/वी/6097 में बताया है कि किराया दरमानों में संशोधन के प्रयोजन से लगाये गये मूल्यांकक ने प्रारूप मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और कि रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए, केओपीटी ने यह बताया है कि मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के पश्चात और न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, वह अपना प्रस्ताव 31 जनवरी, 2018 तक दायर कर देगा। इसलिये, केओपीटी ने शालुक्खली, हल्दिया डाक-II पर, केओपीटी की भूमि की किराया अनुसूची की वैधता में 3 महीने अर्थात् 31 मार्च, 2018 तक या संशोधित अनुसूची की अधिसूचना की तारीख तक, जो भी पहले हो, का विस्तार करने का अनुरोध किया है।

4. शालुक्खली, हल्दिया डाक-II पर, केओपीटी की भूमि की किराया अनुसूची की वैधता 31 दिसम्बर, 2017 को पहले ही समाप्त हो गयी है। केओपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव के संसाधन में लगने वाले अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए और केओपीटी के किराया दरमानों में शून्यता से बचने के उद्देश्य से, वर्तमान दरमानों कि वैधता को 31 दिसम्बर, 2017 से आगे विस्तार करना उपयुक्त समझा जाता है।

5.1. इसके अतिरिक्त, जैसा कि इस प्राधिकरण ने अपने 24 मई 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/40/2011-केओपीटी के द्वारा शालुक्खली, हल्दिया डाक-II पर, केओपीटी की भूमि की किराया अनुसूची की विस्तारित अवधि के दौरान 2% वार्षिक वृद्धि जारी रहेगी।

5.2. यह भी कि, जैसा उक्त संदर्भित आदेश में पहले ही उल्लेख किया गया है, 2% की वार्षिक वृद्धि पट्टा किरायों में शून्यता से बचने के लिये केवल एक अंतरिम व्यवस्था है और कि और कि इस सम्बंध में केओपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर शालुक्खली, हल्दिया डाक-II पर, केओपीटी की भूमि के लिये पट्टा किरयों के निर्धारण को इस प्राधिकरण द्वारा 14 अप्रैल, 2017 के पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जायेगा, जैसा कि भूमि नीति दिशानिर्देश इस प्राधिकरण से प्रत्येक 5 वर्ष पर पट्टा किरायों में संशोधन की अपेक्षा करते हैं।

6. उक्त को देखते हुए तथा ऊपर दिये गये कारणों से और सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण शालुक्खली, हल्दिया डाक-II पर, केओपीटी की भूमि की किराया अनुसूची की वैधता में 31 मार्च, 2018 तक या संशोधित अनुसूची के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, का विस्तार करता है।

टी. एस. वालसुब्रमनियन सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./416/17]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION

Mumbai, the 22th January, 2018

No. TAMP/40/2011-KOPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of Rent Schedule for the land of Kolkata Port Trust at Shalukkhali, Haldia Dock – II as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/40/2011-KOPT

Kolkata Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 19th day of January 2018)

This case deals with the extension of the validity of Rent Schedule for the land of Kolkata Port Trust (KOPT) at Shalukkhali, Haldia Dock - II.

2.1. The existing Rent Schedule of the land of KOPT at Shalukkhali, Haldia Dock - II was approved by this Authority vide Order No. TAMP/44/2011-KOPT dated 14 February 2012. This Order was notified in Gazette of India on 14 March 2012 vide Gazette No.64. The rent schedule came into effect after expiry of 30 days period from the date of notification of the Order in the gazette and is valid for a period of 5 years i.e. upto 13 April 2017.

2.2. Thereafter, the validity of the Rent Schedule for the land of KOPT at Shalukkhali, Haldia Dock - II was extended by this Authority on two occasions to avoid a vacuum in tariff and for the reasons cited in the said Order. On the last occasion, this Authority had extended the validity upto 31 December 2017 *vide* its Order No. TAMP/40/2011 dated 15 September 2017 which was notified in the Gazette of India on 9 October 2017 *vide* Gazette No. 389. While doing so, the KOPT was advised by this Authority to file its proposal for revision of Rent Schedule, latest by 31 October 2017, following the amended Land Policy Guidelines, 2014, issued by the Government.

3. In this backdrop, the KOPT, *vide* its letter no. Ad/E/1032/SD/Shalukkhali/V/6097 dated 28 December 2017 has stated that the valuer engaged for the purpose of revising the Scale of Rents (SOR) has submitted the draft valuation report and that the report is under finalization. In view of this position, the KOPT has stated that it will file its proposal by 31 January 2018 after finalization of the valuation report and with approval of its Board of Trustees. Therefore, the KOPT has requested to extend the validity of current schedule of rent of land of KOPT at Shalukkhali, Haldia Dock – II for a period of 3 months i.e upto 31 March 2018 or upto the date of notification of the revised schedule, whichever is earlier.

4. The validity of Rent Schedule for the land of KOPT at Shalukkhali, Haldia Dock - II has already expired on 31 December 2017. Considering the time required for processing the proposal to be filed by the KOPT and in order to avoid a vacuum in the SOR of KOPT, it is felt appropriate to extend the validity of the existing SOR beyond 31 December 2017.

5.1. Further, as already approved by this Authority in its Order no. TAMP/40/2011-KOPT dated 24 May 2017, the annual escalation of 2% will continue to apply during the extended validity period of the Rent Schedule for the land of KOPT at Shalukkhali, Haldia Dock – II.

5.2. Also, as already indicated in the above referred Order, the annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid vacuum in lease rentals and that the lease rentals to be fixed by this Authority for the land of KOPT at Shalukkhali, Haldia Dock – II, based on a proposal to be filed KOPT in this regard, may have to be given a retrospective effect from 14 April 2017, as the Land Policy Guidelines requires the Authority to fix lease rentals every five years.

6. In view of the above and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing Rent Schedule for the land of KOPT at Shalukkhali, Haldia Dock - II upto 31 March 2018 or till the effective date of implementation of the revised schedule, whichever is earlier. The KOPT is advised to file its proposal for revision of Rent Schedule, latest by 31 January 2018, following the amended Land Policy Guidelines, 2014, issued by the Government.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./416/17]